Indian e-Journal on Teacher Education (IEJTE)
Bi-Monthly e-Journal (Peer Reviewed)
ISSN
2320 –7566

वर्तमान मे कौशल विकास का महत्व और उसकी प्रासंगिकता

डॉ.चंद्रशेखर एन.मोहोड

मातोश्री अंजनाबाई मुन्दाफळे

समाजकार्य महाविद्यालय,नरखेड

==

प्रस्तावना:

भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक रोजगार सृजन है। रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए देश स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे हैं। आवश्यकताओं और बदलती आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाएं शुरू और कार्यान्वित की जाती हैं। इसके द्वारा रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराकर रोजगार की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने का दृष्टिकोण सामने रखा गया है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की अवधारणा के अनुरूप कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र का लक्ष्य सामने रखा गया है. 2022 तक भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा। भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहा है, जो एक बढ़ता हुआ बाज़ार और कुशल जनशक्ति का स्रोत है। इसके लिए हमारे देश में कुशल जनशक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कौशल विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 तक भारत की 64 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग में होगी। भारत में लोगों की औसत उम्र 29 साल होने वाली है. इस पृष्ठभूमि में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए युवा आयु के उम्मीदवारों को बदलती आधुनिक तकनीक के अनुसार कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके उत्पादक बनाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। उद्योग और अन्य क्षेत्र कार्यान्वयन 2010 में शुरू हुआ और वर्ष 2022 तक भारत के लिए 50 करोड़ कुशल जनशक्ति तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र में 4.50 करोड़ कुशल जनशक्ति का कौशल विकास करने का लक्ष्य रखा गया है. 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की 'मेक इन इंडिया' की अवधारणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया नामक कौशल विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है।

इसके अनुरूप, 15 जनवरी, 2015 के सरकारी निर्णय द्वारा पूर्ववर्ती रोजगार एवं स्व-रोज़गार विभाग को परिवर्तित करके महाराष्ट्र में कौशल विकास एवं उद्यमिता का एक अलग विभाग स्थापित किया गया है। 2012 से 2022 तक प्रत्येक जिले में किस क्षेत्र में रोजगार की गुंजाइश (हाई डिमांड सेक्टर) है, इसका अध्ययन कर संस्था एनएसडीसी के माध्यम से रिपोर्ट प्रकाशित की गई। कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 2 सितम्बर 2015 को एक सरकारी निर्णय जारी कर प्रमोद महाजन कौशल एवं उद्यमिता विकास अभियान क्रियान्वित किया जा चुका है। यह अभियान सरकार द्वारा स्थापित महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसायटी मुंबई के माध्यम से क्रियान्वित है और इस संबंध में जिला स्तर की कार्रवाई जिला कौशल विकास रोजगार और उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से की जाती है। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास कार्यकारी समिति का गठन कर कौशल विकास कार्यक्रम की योजना एवं दिशा की समीक्षा की जाती है।

शैक्षिक गुणवत्ता और कौशल विकास:

कौशल और ज्ञान किसी देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। भारत जैसी तेजी से बढ़ती आबादी वाली अर्थव्यवस्था में एक तरफ उच्च प्रशिक्षित गुणवत्ता वाले कुशल संसाधनों की कमी है और दूसरी तरफ आबादी के एक बड़े हिस्से के पास रोजगार योग्य कौशल बहुत कम या कोई नहीं है। शैक्षिक योग्यता के साथ गतिशील और उद्यमशील युवाओं को तैयार करना आवश्यक है जो बदलते समय और कठिन तकनीकी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। संभावित नियोक्ता रोजगार के नजरिए से उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता और कौशल को देख रहे हैं। इसके अलावा, उद्यमियों के पास नए लोगों को आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित करने के लिए न तो समय है और न ही रुचि। प्रतिस्पर्धी युग को ध्यान में रखते हुए, उद्योग केवल कुशल उम्मीदवारों को काम पर रखने के लिए तैयार हैं, जो कंपनी के कल्याण में तुरंत योगदान दे सकते हैं। किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए कौशल एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौशल निर्माण को उत्पादन की दक्षता और उसमें श्रमिकों के योगदान को बेहतर बनाने के साधन के रूप में देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और विकास दर बढ़ाने में कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कारक है। कौशल विकास को व्यक्ति को सशक्त बनाने और सामाजिक स्वीकृति और मूल्य में सुधार करने के एक उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। उच्च और बेहतर कौशल वाला देश वैश्वीकरण की चुनौतियों और अवसरों को प्रभावी ढंग से अपना सकता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत में दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को कुशल जनशक्ति की आपूर्ति करने की क्षमता है। साथ ही भारत अपनी विकास क्षमता के कारण अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। कौशल के आँकड़े बताते हैं कि भारत को कौशल के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक रणनीतिक नीति की आवश्यकता है। कौशल विकास

उद्यमिता राष्ट्रीय रणनीति, 2015 के अनुसार, भारत में कुशल जनसंख्या 4.69%, यूनाइटेड किंगडम में 68%, जर्मनी में 75%, जापान में 80%, दक्षिण कोरिया में 96% है। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1956 में पेश की गई थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 1958 में, आवास नीति 1988 में और राष्ट्रीय श्रम नीति 1966 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति के परिणामस्वरूप, 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई। जिसके जरिए इनोवेटिव फंडिंग मॉडल के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। एनएसडीसी ने 37 संभागीय कौशल परिषदों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई प्रशिक्षण प्रदाता बनाए हैं। जो आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करके उद्योग द्वारा आवश्यक साझेदारी और स्वामित्व की सुविधा प्रदान करेगा। राष्ट्रीय विकास एजेंसी एक समन्वयकारी बल है जो राज्यों में कौशल का समन्वय करने का प्रयास करती है।

भारत के लिए अवसर:

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में से एक है और भारत की कुल आबादी का 62 प्रतिशत हिस्सा श्रमिक वर्ग का है। अगले दशक में इसके और बढ़ने की संभावना है. 2020 तक भारतीय आबादी की औसत आयु 29 वर्ष होने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका में यह 40, यूरोप में 46 और जापान में 47 वर्ष है। औद्योगिक देशों में 2020 तक श्रमिकों की संख्या में 2 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद है। लेकिन भारत में 32 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है. ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के साथ-साथ एक बड़ा अवसर भी है। भारत को रोजगारपरक कौशल और ज्ञान से निर्माण होने की जरूरत है। यह भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। भारत में कौशल निर्माण या कौशल विकास पर आधारित समसामयिक परिवर्तन चीन, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच बदलती जनसांख्यिकीय से पता चलता है कि भारत के पास अगले 20 से 25 वर्षों में 27 मिलियन स्नातक और 20 मिलियन स्नातकोत्तर छात्रों को जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर है रोजगार के लिए शिक्षा से बाहर इन आवश्यक कौशलों की कमी के कारण 15 प्रतिशत से अधिक छात्र रोजगार के योग्य नहीं हैं। भारत अवसर का प्रवेश द्वार है जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रिसाव को रोकने के लिए प्रमुख कौशल का ज्ञान प्रदान करके रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। ऐसे में, भारत में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता बदलते व्यावसायिक और आर्थिक माहौल के लिए आवश्यक कौशल की उन्नति के कारण ही संभव है। गुणवत्ता एवं दक्षता बनाए रखने के लिए यह कार्य चुनौतीपूर्ण है।

वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा की उपलब्धता और अवसर से एक कदम आगे, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का संबंध दैनिक आधार पर उपलब्ध कराने योग्य जनशक्ति के निर्माण से है। सिर्फ डिग्रियां और अंक प्राप्त करने से यह लक्ष्य हासिल नहीं होता। इसीलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। सक्रिय और वैचारिक शिक्षण सोच इसकी नींव है। यह कौशल विकास को बढ़ावा देकर छात्रों की क्षमताओं को विकसित करने में मदद करेगा। हालाँकि कौशल विकास पर दशकों से विचार किया जा रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा पर इसका प्रभाव नगण्य रहा है। ऐसा कौशल के पारंपरिक पाठ्यक्रम का अंतर्निहित घटक न होने के कारण था। अब 'च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम' अनिवार्य करने से कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि इस पद्धति में कौशल विकास की रूपरेखा तैयार की गई है। कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को पारंपरिक पाठ्यक्रम के समकक्ष स्थान दिया गया है। मुख्य योग्यता विकास के अलावा, व्यवसाय को उद्योग में सही जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इक्कीसवीं सदी में यह प्रमुख मुद्दा है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तीव्र और अप्रत्याशित हैं। ऐसे समय में छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के दौरान कौन से कौशल विकसित करने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है. ऐसे समय में अरबों के साथ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि अरबों वाली तकनीक भविष्य की तकनीक है। इस प्रौद्योगिकी विकास की संभावनाएँ असीमित हैं। इसमें हर स्तर पर भाग लेने और योगदान करने के लिए कई चुनौतियाँ और अवसर हैं। कौशल विकास के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण कदम बुनियादी या पूर्व कौशल की आवश्यक और नियोजित वृद्धि है। कौशल बढ़ाने से कर्मचारी परिवर्तन और प्रतिस्पर्धा के समय में व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावी ढंग से और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के सामने, न केवल मौजूदा पेशेवर स्तर पर, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी बढ़े हुए कौशल का कोई विकल्प नहीं है। आज कंपनी-प्रबंधन का चलन और जोर कर्मचारियों को अधिक उन्नत और कुशल बनाने पर है। इसके लिए प्रबंधन द्वारा विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं। कुछ प्रबंधनों द्वारा वार्षिक आधार पर कर्मचारियों के प्रदर्शन को मापने की प्रक्रिया में, वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित कर्मचारी ने अपना काम ठीक से करते हुए क्या नया कौशल हासिल किया है, इसे दर्ज किया जाता है और ध्यान में रखा जाता है। यह कर्मचारी कौशल ग्राफ़ को कर्मचारी से कंपनी स्तर तक संदर्भ के लिए उपलब्ध कराता है, जो निश्चित रूप से प्रभावी है। कुशल या दक्ष कर्मचारियों को नया पद, प्रमोशन जैसे लाभ अवश्य मिलते हैं।

समारोप:

कोरोना के बाद के दौर में कौशल विकास पर और अधिक गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। कोरोना काल के उन लगभग दो वर्षों ने कंपनी और कर्मचारियों के कामकाज और संचालन का चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर अचानक और अप्रत्याशित छँटनी के साथ आए चुनौतीपूर्ण संकट ने कई लोगों के लिए व्यवसाय संचालन से लेकर रोजगार तक बहुआयामी संकट प्रस्तुत किया। यहीं से शुरू हुई वैकल्पिक व्यवसाय, काम की तलाश। आजीविका के रूप में वैकल्पिक कार्य की बात तत्काल सभी को स्वीकार करनी पड़ी। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी कि कंपनी एक नया व्यवसाय ढूंढे और उसे सत्यापित करे और कर्मचारी पारंपरिक काम पर जोर न दें बल्कि लचीली क्षमता के साथ और कभी-कभी बिल्कुल नए कौशल सीखें और हासिल करें और इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और इससे सभी को लाभ हुआ। कोरोना के बाद के दौर में इसकी पुष्टि कई जगहों पर हो रही है. सरकार से तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता के साथ, एक नई लचीली और पारस्परिक कौशल विकास पृष्ठभूमि निश्चित रूप से मौजूद है, विभिन्न कंपनियां अपनी कौशल आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के संबंध में पहल करने की कोशिश कर रही हैं। इन प्रयासों से कंपनियों को कुशल कर्मचारी हासिल करने में काफी फायदा होगा। इसके अलावा, संबंधित उम्मीदवार कौशल अधिग्रहण या कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के बढ़े हुए अवसर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार नई कौशल विकास गतिविधियाँ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होंगी।

संदर्भ-सूची:

आर. ए. दुबे, आर्थिक विकास एवं नियोजन, नेशनल पब्लिशर्स हाउस नई दिल्ली

जैन, एम.के, शोध विधियाँ, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2006

चतुर्भुज मामोरिया भारत की आर्थिक समस्याएँ, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 2007-08

ओ.पी. शर्मा, भारत में नियोजित विकास और आर्थिक उदारीकरण, रामप्रसाद एण्ड संस 2002-03

कटरिया रस्तागी, सांख्यिकी सिद्धान्त एवं व्यवहार पब्लिकेशन मेरठ 1988-89